शिक्षक - रवि शंकर राय, विषय - अर्थशास्त्र
दिनांक - 06-11-2020, वर्ग - BA-III

(2) उद्योग ⇒ सामरिक साम्यवाद की नीति के अन्तर्गत उद्योगों को तेजी से राष्ट्रीयकरण हुआ 28 जून 1918 को जारी 'सामान्य राष्ट्रीयकरण की आज्ञप्ति' द्वारा समस्त औद्योगिक प्रतिष्ठानों को सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया, जिनमें 10 लाख रूबल से अधिक की पूँजी विनियोजित थी। नवम्बर 1920 में जारी आज्ञप्ति के अनुसार उन छोटे-छोटे औद्योगिक प्रतिष्ठानों की भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जिनमें यान्त्रिक शक्ति का प्रयोग होता था और 10 लाख से अधिक श्रमिक काम करते थे। उद्योग धन्धों के राष्ट्रीयकरण से औद्योगिक वस्तुओं का व्यापार निजी-क्षेत्र से निकलकर सरकारी क्षेत्र में आ गया। इससे औद्योगिक प्रशासन का केन्द्रीयकरण भी हो गया। प्रशासकीय नियंत्रण के उद्देश्य से उद्योगों की तीन श्रेणियों में बाँटा गया था (i)

(i) राष्ट्रीय बजार के लिए काम करने वाले मध्यम स्तरीय तथा अत्यधिक स्थानीयकृत उपक्रम। इनका नियंत्रण प्रान्तीय आर्थिक परिषदों को सौंपा गया।

(ii) राष्ट्रीय महत्व के विशालस्तरीय उपक्रम। इनका नियंत्रण 'ग्लावकी' (Glavki) को सौंपा गया, जो सर्वोच्च आर्थिक परिषद का उप-विभाग था।

(iii) स्थानीय बजार के लिए उत्पादन करने वाले लघुस्तरीय उपक्रम। इनका प्रशासन प्रान्तीय आर्थिक परिषदों को सौंपा गया।

कुल मिलाकर, सामरिक साम्यवाद के दौरान सोवियत सरकार की औद्योगिक नीति के तीन मुख्य अंग थे — उद्योगों का तीव्र गति से राष्ट्रीयकरण, उद्योगों पर सरकारी एकाधिकार में वृद्धि तथा औद्योगिक प्रशासन का अत्यधिक केन्द्रीयकरण।

③ व्यापार ⇒ राजकीय पूँजीवाद के दौरान राजकीय एवं निजी व्यापार के सहअस्तित्व का सिद्धान्त अपनाया गया था, जो ठीक ढंग से काम नहीं कर सका तथा व्यापार की मात्रा निरन्तर घटती गई। सामरिक साम्यवाद की नीति के अन्तर्गत उत्पादन एवं उपभोग की सभी वस्तुएं के लिए सरकारी एकाधिकार की स्थापना की गई। नवम्बर 1918 में जारी आज्ञप्ति के

के अन्तर्गत समस्त आन्तरिक निजी व्यापार ~~निषिद्ध~~ निषिद्ध ठहराया गया तथा उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण की जिम्मेदारी 'आपूर्ति विभाग' को सौंपी गई। मार्च 1919 में सहकारी समितियों का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त करते हुए उन्हें आपूर्ति विभाग के अधीन वितरण-तन्त्र में सम्मिलित कर लिया गया। निजी व्यापार के उन्मूलन ~~के~~ से आपूर्ति की वह व्यवस्था पूर्णतः समाप्त हो गई, जो पूंजीवादी प्रणाली की प्रमुख विशेषता थी।

विदेशी व्यापार के क्षेत्र में दिसम्बर 1917 में जारी आज्ञप्ति के अनुसार लाईसेन्स प्रणाली आरंभ की गई थी। आयात-निर्यात के लिए लाइसेंस उन्हीं व्यापारिक प्रतिष्ठानों को दिए जाते थे, जो बहुत दिनों से विदेशी व्यापार में संलग्न थे। अप्रैल 1918 में जारी आज्ञप्ति के अनुसार विदेशी व्यापार के क्षेत्र में 'सरकारी एकाधिकार' की स्थापना की गई, जो बोल्शेविक पार्टी की नीति के अनुरूप था। गृह युद्ध के समय शक्तिशाली राष्ट्रों ने रूस के विरुद्ध आर्थिक नाकेबंदी कर दी, जिसका रूस के विदेशी व्यापार ~~के विकास~~ पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

④ श्रम ⇒ सामरिक साम्यवाद के दौरान, सोवियत सरकार ने श्रमिकों के प्रति कठोर नीति अपनाई दिसम्बर 1918 में जारी आज्ञप्ति के अनुसार 16 से 50 वर्ष तक की आयु वाले समस्त व्यक्तियों के लिए काम करना अनिवार्य बना दिया गया। जनवरी 1920 में जारी आज्ञप्ति द्वारा श्रमिकों की बलात् भर्ती योजना लागू की गई। उनकी आजीविका और कार्य-स्थान में परिवर्तन पर कठोर पाबन्दी लगा दी गई। कार्य से ~~भागने~~ भागने वाले श्रमिकों के लिए दण्ड की व्यवस्था की गई। श्रमिकों की सेनाएं संगठित की गई तथा उनसे कारखाना और सैनिक शिविर में से किसी एक को चुनने के लिए कहा गया। इस तरह सामरिक साम्यवाद के अन्तर्गत उद्योग की तरह श्रम भी राष्ट्रीयकृत हो गया। मजदूरी का ढांचा अत्यधिक स्वेच्छाचारी एवं अस्थिर बन गया, क्योंकि मजदूरी नीति किसी ~~भी~~ निश्चित सिद्धान्त की बजाय आपातकालीन स्थिति से प्रभावित हुई। गृहयुद्ध के परिणामस्वरूप उत्पन्न मुद्रा-स्फीति ने श्रमिकों की स्थिति को और भी दयनीय बना दिया। बाद में चलकर जब सरकार ने वस्तुओं के रूप में मजदूरी का

भुगतान शुरू किया, तब श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार हुआ।

निष्कर्ष :- सामरिक साम्यवाद की नीति द्वारा सोवियत संघ सरकार ने स्वयं को देशी एवं विदेशी शत्रुओं से तो बचा लिया, किन्तु आर्थिक प्रणाली में कई तरह की व्यवस्थाएं उत्पन्न हो गई। यह नीति बाल्शेविक पार्टी के मूलतः उद्देश्य 'सभी के लिए रोटी' किसान के लिए शान्ति एवं भूमि तथा सर्वहारा वर्ग की तानाशाही 'की पूर्ति करने में विफल रही। गृह-युद्ध की समाप्ति पर अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण तथा किसानों का समर्थन प्राप्त करने के लिए सामरिक साम्यवाद की नीति का परित्याग आवश्यक हो गया। अतः मार्च 1921 में सोवियत सरकार ने सामरिक साम्यवाद का परित्याग करते हुए नवीन आर्थिक नीति अपनाई।